

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2022

संख्या लैज.18/2022.— दि हरियाणा लॉज (स्पेशल प्रोविज़नज़) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18**हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2022****हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्य के जिलों के लिए और इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु।”
 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 के वृहत् नाम का प्रतिस्थापन।
3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
 “(4) यह 30 जून, 2025 को प्रभावहीन हो जाएगा।”
 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 1 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—
 (i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 “(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की वैधता की अवधि के भीतर कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वाहन को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा से बाहर करने के लिए पॉलिसी बनाएगी।”;
 2019 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन।
 (ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 “(3) केवल इस आधार पर कि कृषि प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट ऐसे वाहन को दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत किया गया है, राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु किसी विनिर्दिष्ट वाहन के विरुद्ध किसी प्रपीड़क कार्रवाई करने के लिए जारी किए गए सभी नोटिस निलम्बित हो जाएंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से 30 जून, 2025 तक कोई भी प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

बिमलेश तंवर,
 सचिव, हरियाणा सरकार,
 विधि तथा विधायी विभाग।